श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : महोदय, मेरा प्रश्न लाइब्रेरी से ही संबंधित है। एक स्कीम, Scheme for Establishment of Rural Libraries' की घोषणा की गई थी। इस स्कीम को राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के जरिए कार्यान्वित किया जाना था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस स्कीम के अंदर, पिछले वर्ष से ही यह अस्तित्व में है, कितनी राशि आबंटित की गई और गांवों के अंदर कितनी लाइब्रेरीज स्थापित हुईं ? मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार लिटरेसी कैम्पेन से इसे जोड़कर इस स्कीम की मूल भावना को, मूल उद्देश्य को दरकिनार कर दिया गया है। इस संबंध में मंत्री महोदय् के पास क्या इन्फोर्मेशन है ? मेरा दूसरा सवाल यह है कि चूंकि स्कूल में बिल्डिंग्स की बात आई है तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि एम.पी. लैड के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में जो स्कूल बिल्डिंग्स बनी हैं उनके रख-रखाव के लिए क्या केन्द्र सरकार अलग से राशि आवंटित करने पर विचार कर रही है ?

डा. मुरली मनोहर जोशी : उपसभाध्यक्ष जी, यह प्रश्न संबंधित सवाल के संदर्भ में नहीं उठता इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

AFRO-Asian Games

*563. PROF. M. SANKARALINGAM : Will the Minister of YOUTH AFFAIRS AND SPORTS be pleased to state :

(a) the total expenditure to be incurred on the Afro-Asian games to be held this year ;

(b) whether Government would consider holding the games in other major cities, apart from New Delhi;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SUSHREE UMA BHARTI) : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Based on the initial estimates made by the Indian Olympic Association, a provision of Rs. 30.00 crores for upgradation of infrastructure and procurement of equipment and Rs. 20.00 crores for the conduct of the Games has so far been made by the Government. However, an assessment of the additional expenditure likely to be incurred for the Games is being made on the basis of the budget estimates prepared by various committees of the Afro-Asian Games.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) These Games have been allotted to the city of New Delhi only.

PROF. M. SANKARALINGAM : Sir, the statement does not reveal the required information. Part (b) of my question was, whether the Government would consider holding the games in other major cities, apart from New Delhi; the answer given is, 'No'. Part (d) of my question was, "if not, the reasons therefor"; but no reason has been given to that effect. Therefore, I would like to know what is the reason behind it. Nowadays, both the young and the elder people, across our society, evince a keen interest in playing various sports or watching various sports events. Hence, it is imperative to organize such international events in Calcutta, Bombay and Madras also so that the people who are interested in sports would have an opportunity to witness these games. At the same time, the sportsmen will also be able to assess the interest exhibited by these people. Will the Government consider it?

सुश्री उमा भारती : उपसभाध्यक्ष महोदय, एफ्रो- एशियन, 2001 गेम्स भारत के लिए और भारत में दिल्ली सिटी के लिए एलोट हुए हैं। इनको मार्क करके, चिन्हित करके दिल्ली शहर के लिए एलोटमेंट किया गया है। माननीय सदस्य ने जो कहा है उसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार का विचार जो हमारे एक्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें भी आया था और हमने उसी समय यह स्पष्ट कर दिया था कि ये गेम्स दिल्ली सिटी में ही आयोजित होंगे। दिल्ली के बाहर कोई भी कम्पीटीशन हम नहीं ले जा सकते।

PROF. M. SANKARALINGAM : Mr. Vice-Chairman, Sir, various reports are appearing in the newspapers. Only yesterday, there was a news item in the "Indian Express" which said, "A Memorandum of Understanding to this effect was signed by Afro-Asian Games Organising Committee Secretary-General, Shri Randhir Singh, and the Chairman and Managing Director, ITDC, Shri Ashwani Lohani." I would like to know what are the terms of that agreement and what is the purpose of that agreement.

सुश्री उमा भारती : उपासभाध्यक्ष जी, इन्होंने एफ्रो-एशियन गेम्स के एक्सपेंडीचर के बारे में सवाल पूछा है। एम.ओ.यू. के एग्रीमेंट की टर्म आफ रेफरेंसेस क्या हैं वे इस सवाल की परिधि में कहीं नहीं आते हैं। आई.टी. डी. सी. के सी. एम. डी. के साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सेकेट्री जनरल ने एक एम.ओ.यू. साइन किया है। अगर आप आज्ञा दें तो माननीय सदस्य की जानकारी के लिए इसे प्रस्तुत कर सकती हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : बाद में कर दीजिएगा।

श्री रवि शंकर प्रसाद : आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, मंत्री जी से इस आयोजन के [illegible] संबंध में मेरा सवाल है। यह जो आयोजन हो रहा है उससे देश की इज्जत कितनी बढ़ेगी यह दखना है। पूर्व में भी आयोजन हुए हैं कॉमन वेल्थ गेम्स हुए, एशियन गेम्स हुए और खेलों में भारत का स्तर क्या है यह हम सबके सामने है। जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में मेडल नहीं मिलता तो देश को कितनी निराशा होती है यह मंत्री जी समझती होंगी, देश समझता है। आपके उत्तर मे स्पष्ट है, इसमें आपने बताया है कि 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे व्यवस्थाओं और उपकरणों की आपूर्ति में और 30 करोड़ रुपये खेलों के आयोजन में खर्च होंगे। मेरे प्रश्न के दो भाग हैं, "अ" भाग यह है कि क्या इसका पूरा खर्चा भारत सरकार देगी अथवा इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन, जो बड़ी एसोसिएशन है, जिसके पास काफी पैसा है उन्होंने भी कुछ खर्चा देने के बारे में आश्वासन दिया है और अगर दिया है तो कितना दिया है ?

दूसरा प्रश्न है असेसमेंट के बारे में । अतिरिक्त व्यय के बारे में आप क्या करने वाले हैं ? यह कुल कितना खर्च होने वाला है तथा इस पूरे खर्च में भारत सरकार का और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कितना व्यय है ?

सुश्री उमा भारती : सर, जो माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं बाद के प्रश्न का उत्तर पहले देना चाहती हूं क्योंकि इसके संदर्भ में उसका तारतम्य बन रहा है। बजट का जो अंतिम अनुमान है वह अभी तक आना बाकी है। जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनी है, उसके अन्तर्गत करीब 22 उपसमितियां हैं जो काम कर रही हैं और इन उपसमितियों के बजट निरन्तर प्रस्तुत हो रहे हैं। बजट प्रस्तुतीकरण में देर इसलिए हो रही है, मैं भारत के सर्वोच्च सदन के सामने यह बताना चाहती हूं कि जो यह खेल होने हैं, इसके बारे में जो फाइनल निर्णय हुआ, वह 25 अप्रैल को हुआ था और 25 अप्रैल से अभी तक जो प्रक्रिया हुई, उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनी, एक्जीक्यूटिव बोर्ड बना और इनकी बैठकें हुईं। इन बैठकों के बाद वे अपना बजट प्रपोजल सम्मिट करने जा रहे हैं। इसका प्रारम्भिक बजट प्रस्ताव जो था, वह 70 करोड़ का था, जिसमें से 3 करोड़ अधो-संरचना में खर्च किए जाएंगे और 40 करोड़ खेलों के संचालन और उनकी व्यवस्थाओं में खर्च होंगे। ज़ब आर्गेनाइजिंग कमेटी नहीं बनी थी तब कैबिनेट में यह प्रपोजल गया था और उसमें इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन ने कहा था कि हम फंड रेज करके, उनके पास कितना बैंक बैलेंस है, हमें नहीं मालूम लेकिन उन्होंने कहा कि हम 20 करोड़ रुपए देंगे। सर, अब आर्गेनाइजिंग कमेटी है, खेलों के संचालन का जो दायित्व है, कंडक्ट ऑफ गेम्स का दायित्व जो है वह संचालन समिति के ऊपर है। अंतिम बजट का जो अनुमान है वह अभी आना शेष है। करीब दो महीने पहले वित्त मंत्रालय के साथ खेल मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक हुई थी और हम दोनों मंत्रियों की भी बैठक हुई थी । उसमें हमने कहा था कि बजट अनुमान अभी बढ़ने की संभावना है। लेकिन यह

अनुमान कितना है इसको सुनिश्चित हम तब तक नहीं कर पायेंगे जब तक सभी कमेटियां अपना बजट प्रस्तुत नही करेंगी। फाइनेंस कमेटी, जो एफ्रो-एशियन गेम के लिए बनी है, उसके माध्यम से वे हमारे सामने अपना बजट प्रस्तुत करेंगी और अंतिम अनुमान लगाकर वह वित्त मंत्रालय के सामने प्रस्तुत होगा।

श्री रवि शंकर प्रसाद : मेरे प्रश्न के पहले भाग का, जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन के बारे में था, उसका उत्तर नहीं आया।

सुश्री उमा भारती : अभी मैं उसका उत्तर दे दूंगी।

श्री सतीश प्रधान : महोदय, मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है कि अखबारों में न्यूज आती है कि एफ्रो-एशियन गेम्स के लिए स्पांसर्स नहीं मिल रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विषय में सच्चाई क्या है, मंत्री जी क्या इस विषय पर जानकारी दे पायेंगे ? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि एफ्रो-एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों का जो परफारमेंस होना चाहिए उसके लिए हमारे मंत्रालय ने या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने क्या कोई प्रोविजन कर रखा है, अगर कर रखा है तो क्या कर रखा है और उसका किस ढंग से विनियोग होगा ?

सुश्री उमा भारती : सर, जो पहली बात थी, असल में मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे दिया था। प्रारम्भ में आईओए ने लिखित प्रस्ताव भेजा था कि वह हमको 20 करोड़ रुपया रेज करके देंगे। अभी तक इसके बारे में कोई अंतिम अनुमान प्रस्तुत नहीं हुआ है। सब-कमेटी के साथ बात चल रही है। इसलिए इस बारे में मैं कोई सुनिश्चित बात नहीं कह सकती हूं। लेकिन उनके सेक्रेटरी जनरल का एक पत्र जरूर आया था, जब संचालन समिति नहीं बनी थी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नहीं बनी थी।

श्री सतीश प्रधान : मैंने · · ·

सुश्री उमा भारती : माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है मैं उस पर आ रही हूं।

श्री सतीश प्रधान : स्पांसर्स जो भी पैसा देने वाले हैं वह ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को देंगे, इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन को नहीं देंगे।

सुश्री उमा भारती : ऐसा नहीं है कि स्पांसर्स नहीं मिल रहे हैं। स्पांसर्स मिल रहे हैं। हमारी पीएसयूज के साथ बात चल रही है, प्राइवेट सेक्टर के लोगों के साथ बात चल रही है। सर, मैं एक बार फिर इसको रिपीट करूं कि इन गेम्स की अंतिम क्लियरेंस जो हुई है वह 25 अप्रैल को हुई है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि 25 अप्रैल से लेकर अब तक बहुत कम समय हमको मिला है और

उनमें भी तीन महीने मानसून के हैं, बरसात के हैं। मैं तो यह मानती हूं कि जिस प्रकार से हमारे यहां काम हो रहा है, सैटरडे, सन्डे की छुट्टियां हम बिल्कुल भूल गए हैं। अधिकारी भूल गए हैं कि सैटरडे सन्डे भी कोई होते हैं। रात-दिन अपने पांव पर खड़े होकर सभी लोग निरंतर काम में लगे हुए हैं। स्पांसर्स की जहां तक बात है, स्पांसर्स ने एप्रोच किया है। इसमें दो हिस्से हैं, एक मारकेटिंग का जो हिस्सा था इसमें दूरदर्शन टेलीविजन को जो टीवी मारकेटिंग थी उसमें हमने प्रसार भारती के साथ करार किया है। बाकी की जो मारकेटिंग है उसके लिए टेंडरिंग की प्रोसेसिंग हो रही है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं माननीय उपसभाध्यक्ष जी आपके माध्यम से सदन को कि हम चूंकि सरकार हैं इसलिए हमें बहुत सारी प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करना पड़ता है और उन प्रक्रियाओं तथा नियमों का एक समय होता है। उस समय से पहले हम कितनी भी कोशिश करें उस समय से पहले किसी डिसिजन पर नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट देने का एक समय सुनिश्चित है, जब बिड्स आती हैं उनके साथ नेगोशिएंशस के स्टेप्स हैं। इसलिए इन सब स्थितियों के चलते हुए हमें तैयारियों के लिए थोड़ा समय लगेगा वैसे समय ही हमारे पास कम है। मैं बताना चाहती हूं कि स्पांसर्स मिल रहे हैं, लोगों ने एप्रोच किया है, पी एस यूज के लोग भी हमारी सहायता कर रहे हैं। कल ही हमें एक पत्र मिला है पैट्रोलियम सेक्टर से, उन्होंने स्वयं 5 करोड़ की स्पांसरशिप अपनी तरफ से आफर की है। इस प्रकार से प्रायवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की तरफ से हमें स्पांससरशिप के खूब आफर हैं और उसमें कोई कमी नहीं है। एक दो दिन में जो मारकेटिंग का शेष हिस्सा है उसकी भी घोषणा हो जाएगी ... (**व्यवधान**)

श्री सतीश प्रधान : माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसका जबाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि हमारे खिलाड़ियों के अच्छे परफारमेंस के विषय में हमने क्या प्राविजन किए हैं—आर्थिक और प्रशासनिक ?

सुश्री उमा भारती : वैसे, यह सवाल उसकी परिधि में नहीं आता है इसलिए मैं उत्तर नहीं दे रही थी। फिर भी मैं बता दूंगी। हमारे यहां पर परफारमेंस को देखने का जो काम है वह फेडरेशन का है। मैंने कई बार सदन में यह निवेदन किया है कि अथारिटी आप हमें कुछ नहीं देते हैं और परफारमेंस दे देते हैं। खेलों के परफारमेंस को ठीक करने का जो काम है वह फेडरेशन का है। फिर भी सर, जो भी खिलाड़ी परफार्म करने वाले हैं, आठ डिसिप्लिन्स में, एफ्रो-एशियन गेम्स में, उनकी दो जगह पर ट्रेनिंग चल रही है—बंगलौर और पटियाला में। हमने स्वयं तय किया है, मैंने स्वयं तय किया है कि मैं स्वयं उन खिलाड़ियों से एक-एक करके मिलूंगी और मिलती जा रही हूं। उनके, उनके कोचेज और फेडरेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वे हम उनको पूरी की पूरी दे सकें—खिलाड़ियों के तैयारियों में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। यह सवाल प्रश्न की परिधि से बाहर का था।

डा. कुमकुम राय : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। हमारे यहां जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनमें से पदक लाने वाले खिलाड़ियों की संख्या बहुत कम है। अभी हाल में हम लोगों ने अखबार में पढ़ा कि कुंजू रानी पर प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का आरोप लगा। उन पर जो ये आरोप लगे हैं उन्होंने बाद में फिर विशेष परीक्षण की मांग इस संबंध में की है। तो इस संबंध में इस आरोप को पुष्ट करने के लिए क्या आप कोई विशेष परीक्षण करवाने के लिए सोच रही हैं ?

सुश्री उमा भारती : यह जो माननीय सदस्य का सवाल है, यह मूल प्रश्न की परिधि से बहुत-बहुत दूर है।

श्री राजीव शुक्ल : उपसभाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि 20 करोड़ रुपया इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन रेज करेगी—यानी कि मारकेट से रेज करके देगी। आर्थिक मंदी की जो हालत है और मारकेट की जो स्थिति है उसमें अगर आई ओ ए इस धन को रेज करने की स्थिति में नहीं हो पाता है, रेज नहीं कर पाता है तो इसकी भरपाई मंत्री जी कहां से करेंगी ?

सुश्री उमा भारती : ऐसा कोई तय नहीं हुआ था। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि हम मारकेट से करके देंगे। यह कहा था कि हम रेंज करके देंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब खेलों का जो पूरा दायित्व है वह आर्गेनाइजिंग कमेटी के ऊपर है और आर्गेनाइजिंग कमेटी अपने इन प्रयासों में निरंतर लगी हुई है कि हम कम से कम बजट करें। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहती हूं सर, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो स्पष्ट हो जाएं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि अभी पूसान में एशियन गेम्स, 2002 की तैयारी हो रही है। उसमें वे 2,500 करोड़ रुपए तो स्टेडियम पर खर्च कर रहे हैं और 1,500 करोड़ रुपए खेल के संचालन पर खर्च कर रहे हैं। हमने यह संकल्प किया हुआ है यद्यपि अंतिम बजट के अनुमान बाकी हैं लेकिन जो लगभग सब कमेटियों के बजट तैयार हो रहे हैं उस हिसाब से जो अंदाज आ रहा है, जो अंतिम अंदाज नहीं है, वह यह है कि हम 150 करोड़ रुपए से ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। सर, नेशनल गेम्स भी होते हैं तो कई सौ करोड़ के लगभग खर्च हो जाते हैं। एशियन गेम्स के ऊपर एक तरफ 1,500 करोड़ रुपए खेलों के संचालन पर और 2,500 करोड़ रुपए स्टेडियम पर—सिर्फ एशियन गेम्स पर और भारत में अफ्रो-एशियन गेम्स यानी अफ्रीका और एशिया दोनों कान्टीनेन्ट्स के गेम्स के ऊपर 150 करोड़ · · · ।

हम इस बात के लिए संकल्पबद्ध हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह कहा है कि ये खेल देश की प्रतिष्ठा का सवाल हैं। अब ये खेल, खेल मंत्रालय और आईओए की इज्जत का ही सवाल नहीं है, बल्कि देश के नागरिकों का, देश की प्रतिष्ठा का, देश के नौजवानों और खिलाड़ियों के

सम्मान का सवाल इसके साथ जुड़ गया है। इसलिए हम संकल्पबद्ध हैं कि फिजूलखर्ची नहीं करेंगे लेकिन हम भव्यता का और भारत की आतिथ्य परंपरा का पूरा ध्यान रखेंगे। खेल के संचालन में खिलाड़ियों को कोई शिकायत न रहने पाए इसका भी हम पूरा-पूरा ध्यान रखेंगे, यह मैं सदन से निवेदन करना चाहती हूं। लेकिन यह ध्यान रहे कि समय हमें बहुत कम मिला है और चुनौती हमें बड़ी दी गई है, इसलिए हम तो सदन का आशीर्वाद चाहते हैं कि इस चुनौती का हम मुकाबला कर सकें और समय कम होते हुए भी सर्वोत्तम तरीके से इन खेलों को संचालित कर सकें।

Private Catering on Trains

*564. SHRI BHAGATRAM MANHAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of trains on which private catering has been allowed;

(b) the details of contractors and the other trains on which the same contractors have been permitted to do catering, without calling for tenders/bids; and

(c) the number of complaints received against these contractors from Members of Parliament and other VIPs and the action against them ?

MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) 124 pairs of trains.

(b) Details of 51 private contractors managing pantry car services are given in Statement–I.

Details of pantry car contractors permitted to do catering on other trains without calling for tenders/bids and reasons thereof are given in Statement–II.

(c) Nine complaints were received in the period from March 2000 to July 2001. Punitive action has been taken against the licensees including imposition of fines in case of substantiated complaints.